

32. उच्च न्यायालय

राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य (प्रधान) पीठ कहाँ है? [पटवार-23.10.2021 (Shift-II)][जेल प्रहरी -2017]

[कारापाल- 2012][राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-14.07.2018 (II)]

(1) उदयपुर (2) जयपुर (3) जोधपुर (4) अजमेर

Ans. (3)

व्याख्या - 8 दिसम्बर, 1976 को राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 1977 एक खण्ड पीठ की जयपुर में स्थापना की।

निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई-

[I Grade (Pol. Science) - 06.01.2020]

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-13.05.2022 (II)]

(1) 1 नवम्बर, 1956 (2) 8 दिसम्बर, 1976

(3) 26 फरवरी, 1958 (4) 8 मई, 1950

Ans. (2) व्याख्या - उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? [जेल प्रहरी परीक्षा 29-10-2018, Shift-I]

[प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021]

(1) 31 जनवरी, 1977 (2) 31 जनवरी, 1978

(3) 31 जनवरी, 1978 (4) 31 अक्टूबर, 1977

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा.....में किया गया था।

[कॉलेज व्याख्याता (सारंगी) 30.5.2019][CET : 08.01.2023 (S-I)]

(1) 29 अगस्त, 1949 (2) 28 जनवरी, 1950

(3) 27 मार्च, 1951 (4) 28 जनवरी, 1952

Ans. (1)

व्याख्या- संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त, 1949 को जयपुर में किया गया। मुख्य न्यायाधीश कमलकान्त वर्मा बनाया गया। नवम्बर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया।

□ निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त, 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? [Asst. Professor- 7.1.2024]

(1) श्री जय नारायण व्यास

(2) राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह

(3) माननीय न्यायमूर्ति जवानसिंह राणावत

(4) माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा

Ans. (2) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? [CET : 05.02.2023 (S-II)]

(1) गिरधारी लाल व्यास समिति (2) मधुकर गुप्ता समिति

(3) सुरेश माथुर समिति (4) सत्यनारायण राव समिति

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम, 1952 प्रभावी हुए- [Assistant Professor-22.9.2021]

(1) 16 जनवरी, 1952 (2) 15 अगस्त, 1952

(3) 01 अक्टूबर, 1952 (4) 31 दिसम्बर, 1952

Ans. (3)

व्याख्या - राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम, 1952 जो 01 अक्टूबर, 1952 से प्रभावी हुए। उसमें 8 भाग, 39 अध्याय एवं 924 नियम हैं।

□ राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त, 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है- [Assistant Professor-22.9.2021]

(1) न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर- जोधपुर

(2) न्यायमूर्ति कैवर लाल बापना - जयपुर

(3) न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत - कोटा

(4) न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त - बीकानेर

Ans. (3) न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता - कोटा

□ आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नव निर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर पाँच उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान उनमें से एक नहीं है? [राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-15.05.2022 (II)]

(1) जयपुर

(2) जोधपुर

(3) कोटा

(4) बीकानेर

Ans. (*)

व्याख्या - नव निर्मित राज्य में, पाँच उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर (कोटा में एक बेंच के साथ संयुक्त राजस्थान की राजधानी होने के नाते) और अलवर (मत्स्य राज्य की राजधानी होने के नाते) में 20 न्यायाधीशों की कुल संख्या के साथ कार्य कर रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने इन विभिन्न न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया।

- निम्नलिखित में से कौनसा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता है- [प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021]

(1) भीलवाड़ा (2) अजमेर (3) बारां (4) अलवर

Ans. (1)

व्याख्या - जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच की स्थापना पूर्व आदेश द्वारा अजमेर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जयपुर, झुन्झुनू, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, टोंक और दौसा के जिलों में होने वाले मामलों के संबंध में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया है। शेष 18 जिले जोधपुर प्रधानपीठ के क्षेत्राधिकार में रखे गए।

- जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं-

[CET : 05.02.2023 (S-II)]

- (1) मुख्यमंत्री द्वारा (2) राज्यपाल द्वारा
(3) भारत के राष्ट्रपति द्वारा
(4) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

Ans. (2)

व्याख्या- जिला न्यायाधीश : संविधान के अनुच्छेद 233 (1) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है।

दूसरा अनुच्छेद 233 (2) के अनुसार जो व्यक्ति केन्द्र या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम सात वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, साथ ही उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल, जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है किन्तु ऐसे व्यक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं।

- राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, के द्वारा की जाती है

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-14.06.2024 (I & II)]
[Assistant Professor-22.9.2021]

- (1) भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा
(2) राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद् के साथ परामर्श कर राज्यपाल द्वारा
(3) राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श
(4) राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा

Ans. (1)

व्याख्या - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति - अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षरों व मुहर से जारी वारंट द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के उपरान्त की जाती है तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण हेतु कॉलेजियम प्रणाली प्रचलन में हैं, जिसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कॉलेजियम के चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह-मशविरा करना होता है।

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह-मशविरा करना होता है-[School Lecturer (Sans. Edu.)-04.08.2020]

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

- उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है?[Asst. Jailer-15.3.2016][CET-11.2.2023]

(1) राज्यपाल (2) मुख्यमंत्री (3) राष्ट्रपति (4) प्रधानमंत्री

Ans. (3)

व्याख्या - त्यागपत्र / अनुच्छेद 217(1)क-राष्ट्रपति
को लिखित एवं हस्ताक्षरित त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं।

1 भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है?

[Protection Officer-28.1.2023]

- (1) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा
- (2) भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा
- (3) राष्ट्रपति के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
- (4) राज्यपाल के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

Ans. (2)

व्याख्या - अनुच्छेद 217 (3) के अनुसार 'यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा।'

1 संविधान के कौनसे अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं?

[कॉलेज व्याख्याता परीक्षा-2016]

- (1) अनुच्छेद 214 से 231 (2) अनुच्छेद 227 से 232
- (3) अनुच्छेद 233 से 237 (4) अनुच्छेद 234 से 240

Ans. (3)

व्याख्या - अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान
(संविधान भाग VI, अनुच्छेद 233-237)

- अनुच्छेद 233 : जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- अनुच्छेद 233क : कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमाम्यकरण।
- अनुच्छेद 234 : न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती।
- अनुच्छेद 235 : अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।
- अनुच्छेद 236 : निर्वाचन
- अनुच्छेद 237 : कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना।

1 राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? [JEN (Mechanical) Diploma-20.05.2022]

[RPSC कनिष्ठ लेखाकार-2 अगस्त, 2015]

[मूल्यांकन अधिकारी-23.08.2020][CET : 07.01.2023 (S-II)]

- (1) 27 (2) 35 (3) 50 (4) 45

Ans. (3)

व्याख्या-वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीश हैं।

1 अनुच्छेद-प्रावधान सुमेलित कीजिए-[RAS-26.10.2013]

- (A) 215 (i) किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण
- (B) 222 (ii) सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति
- (C) 226 (iii) कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
- (D) 227 (iv) उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता

कूट: A B C D कूट: A B C D

- (1) (iv) (i) (iii) (ii) (2) (ii) (i) (iii) (iv)
- (3) (i) (iv) (iii) (ii) (4) (iv) (ii) (iii) (i)

Ans. (1)

व्याख्या - अनुच्छेद 215 : उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना।

अनुच्छेद 222 : किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण।

अनुच्छेद 226 : कतिपय याचिकाएँ जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

अनुच्छेद 227 : सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति।

1 उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट (याचिका) जारी कर सकते हैं-

[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-13.06.2024 (II)]

- (1) 220 (2) 221 (3) 213 (4) 226

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

1 राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन हैं?

[पटवार-24.10.2021 (II)][उद्योग प्रसार अधिकारी-22.08.2018]

- (1) कैलाश नाथ वाँचू (2) सरजू प्रसाद
- (3) जे. एम. पांचाल (4) शरत कुमार घोष

Ans. (1)

व्याख्या : राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश :

मुख्य न्यायाधीश	अवधि
1. कमला कान्त वर्मा (प्रथम)	1949-1950
2. कैलाश नाथ वाँचू (सर्वाधिक)	1951-1958
3. सरजू प्रसाद	1959-1961
4. जे.एस. रानावत	1961-1963
5. डी.एस. दवे	1963-1968
6. दौलत मल भण्डारी	1968-1969
7. जे. नारायण	1969-1973
8. बी.पी. बेरी	1973-1975
9. पी.एन. सिंघल	1975-1975
10. वी.पी. त्यागी	1975-1977
11. सी. होत्रिया	1978-1978
12. चान्द मल लोढ़ा	1979-1980
13. के.डी. शर्मा	1981-1983
14. पी.के. बनर्जी	1983-1985
15. डी.पी. गुप्ता	1986-1986
16. जे.एस. वर्मा	1988-1989
17. के.सी. अग्रवाल	1990-1994
18. जी.सी. मित्तल	1994-1995
19. ए.पी. रावानी	1995-1996
20. मुकुल गोपाल मुखर्जी	1996-1997
21. शिवराज वी. पाटिल	1999-2000
22. ए.आर. लक्ष्मणन	2000-2001
23. अरुण कुमार	2001-2002
22. अनिल देव सिंह	2002-2004
25. सच्चिदानन्द झा	2005-2007
26. जे.एम.पांचाल	2007-2007
27. नारायण राव	2008-2009
28. दीपक वर्मा	2009-2009
29. जगदीश भल्ला	2009-2010
30. अरुण कुमार मिश्रा	2010-2012
31. अमिताव रॉय	2013-2014
32. सुनील अम्बवानी	2015-2015
33. सतीश कुमार मित्तल	2016-2016
34. नवीन सिन्हा	2016-2017
35. प्रदीप नन्दाजोग	2017-2019
36. श्रीपति रवींद्र भट्ट	2019-2019

37. इंद्रजीत महांती	2019-2021
38. अकील कुरैशी	2021-2022
39. एस.एस. शिन्दे	2022-2022
40. पंकज मिथल	2022-2023
41. आगस्टाइन जॉर्ज मसीह	2023-2023
42. महेन्द्र मोहन श्रीवास्तव	06.2.2024 से..

□ निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? [मूल्यांकन अधिकारी, 2020]

- (1) जे. एस. वर्मा (2) अरुण कुमार
(3) जे. एम. पांचाल (4) विरेन्द्र कुमार सिंघल

Ans. (4) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे- [ANM-03.02.2024][पटवारी प्रारम्भिक-2021]

- (1) के. के. वर्मा (2) डी.एस. दवे
(3) सरजू प्रसाद (4) इनमें से कोई नहीं

Ans. (1) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ न्यायमूर्ति आगस्टाइन जॉर्ज मसीह, राजस्थान हाइकोर्ट के...वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। [सूचना सहायक - 21.1.2024]

- (1) 43 (2) 40 (2) 41 (4) 42

Ans. (3) व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

□ राज्य के प्रथम वर्जुअल कोर्ट का ई-उद्घाटन किसने किया?

[वनपाल-06.11.2022(S-I)]

- (1) अशोक गहलोत (2) ओम बिरला
(3) एस.एस. शिन्दे (4) कलराज मिश्रा

Ans. (3)

व्याख्या - 20 जुलाई, 2022 को तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिन्दे ने पहली वर्जुअल अदालत का ई-उद्घाटन किया।

□ जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई?

[III Grade (Punjabi) -28.2.2023]

- (1) 24 जनवरी, 2007 (2) 29 दिसम्बर, 2008
(3) 16 नवम्बर, 2005 (4) 27 अक्टूबर, 2009

Ans. (1)

व्याख्या - राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी - यह राजस्थान उच्च न्यायालय की अकादमिक शाला है जो न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन हेतु कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इसकी स्थापना 24 जनवरी, 2007 को जोधपुर में हुई।